Date: 08-09-2021
Publication: Sanmarg
Edition: Ranchi

कोल इंडिया खिलाड़ियों के छात्रावास निर्माण में देगा फंड

संवाददाता

रांची : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने देश में खेल के बुनियादी ढांचे को और बेहतर करने के उद्देश्य से मंगलवार को नई दिल्ली में खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय, के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया। एमओयू पर सीआईएल की ओर से कार्मिक निदेशक विनय रंजन, युवा मामले और खेल निदेशक विजय कुमार एवं सदस्य सचिव ने हस्ताक्षर किए।

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक, भारत सरकार की गरिमामयी उपस्थि?ति में यह एमओयू किया गया। मौके पर डॉ अनिल कुमार जैन सचिव (कोयला), रवि मित्तल, सचिव (खेल), प्रमोद अग्रवाल, अध्यक्ष, सीआईएल, अतुल सिंह, संयुक्त सचिव (खेल-विकास) एवं अन्य(उपस्थित थे। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सीआईएल अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) की ओर से 75 करोड़ रुपये का योगदान दिया जायेगा। इस राशि का उपयोग खिलाड़ियों के लिए बने तीन अत्याधुनिक छात्रावासों के निर्माण के लिए किया जाएगा। वतर्मान में ओलंपिक और पैरालिंपिक के क्षेत्र में मिली सफलता को देखते हुए इस पहल को अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है। मालूम हो भारत का खेल के क्षेत्र में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है । 350 खिलाड़ियों की संयुक्त क्षमता के साथ इन छात्रावासों का निर्माण लक्ष्मीमबाई नेशनल इंस्टीरच्यूहट ऑफ फिजिकल एजुकेशन (एलएनआईपीई), ग्वालियर एवं भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के भोपाल और बेंगलुरु के सेंटर में किया जाएगा। इन सेंटरों में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण दिया जायेगा। इससे निश्चय ही प्रतिभाशाली एथलीट्स सीधे लाभांवित होंगे। यह परियोजना वर्ष 2023 तक पूरी हो जायेगी जिसके लिए सीआईएल पहले ही 25 करोड़ रुपये की राशि जारी कर चुकी है। सीआईएल का यह पहल भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के उद्देश्य को भी सार्थक करता है।

मालूम हो कि सीआईएल अपने सीएसआर गतिविधियों में वार्षिक 500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करता है। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों ने खेल प्रोत्साहन के क्षेत्रों में कुछ उच्च प्रभाव वाली परियोजनाएं शुरू की हैं। उनमें से झारखंड सरकार एवं सीसीएल की संयुक्त पहल से संचालित खेल अकादमी, रांची - झारखंडर स्टेट स्पोटर्स प्रमोशन सोसाईटी (जेएसएसपीएस) उल्लेखनीय उदाहरण है। जिसको सालाना 10 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता की जाती है। साथ ही मल्टी पर्पस स्पोनटर्स कॉम्पजलेक्स, संबालपूर, ओडिसा को 25 करोड़ रूपये एवं झारसुगुडा, ओडिशा में 10,000 क्षमता वाला स्टेडियम के लिए 23 करोड़ रूपये की सहायता भी उल्लेखनीय है।

***Date*:** 10-09-2021
***Publication*:** Dainik Jagran
***Edition*:** Dhanbad

90 हजार हेक्टेयर जमीन को ग्रीन कवर जोन बनाएगी कोल इंडिया

सीसीएल, बीसीसीएल व ईसीएल के दो दर्जन स्थल चिह्नित

दैनिक जागरण एक्सक्लूसिव

आशीष अंबष्ठ ● धनबाद

कोयले के कारण देश के आठ राज्यों के कई जिले प्रदूषण की चपेट में है। इसमें झारखंड के धनबाद, बोकारो, गिरीडीह, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग आदि जिले शामिल हैं। अब कोयला कंपनियां इन जिलों में प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन कवर बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। कोयला मंत्रालय खुद इसकी निगरानी कर रहा है।

सभी कोयला कंपनियों से प्लान रिपोर्ट भी कोल इंडिया के मार्फत तैयार कर मांगा गया है। राज्य में कोल इंडिया की तीन बड़ी कंपनियां बीसीसीएल, ईसीएल व सीसीएल शामिल हैं। बीसीसीएल की गोविंदपुर, अकाशकिनारी, लोदना सिजआ, क्षेत्रों को मिलाकर करीब 90 हेक्टेयर जमीन ग्रीन कवर जोन के लिए चिन्हित की गई है। वहीं ईसीएल के मुगमा, गोड्डा के ललमटिया, देवघर के चितरा व जामताड़ा साइडिंग क्षेत्र का चयन किया गया है। कोयला कंपनियों ने अब तक 13.5 करोड़ पेड़ लगाने का दावा किया है।

56 हजार हेक्टेयर जमीन पर अबतक लगाए जा चुके हैं पौधे

प्रदूषण से लड़ाई

- कोयला मंत्रालय ने सभी कोयला कंपनियों से मांगी प्लान रिपोर्ट
- बीसीसीएल की 90 हेक्टेयर जमीन इसके लिए चिह्नित की गई

वर्ष 2019-20 में 1,853 हेक्टेयर भूमि पर लगाए पौधे

कोयला मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि गत वर्ष 1,853 हेक्टेयर जमीन को ग्रीन कवर किया गया है। इसके लिए सभी कोयला कंपनियों को विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है।

सालाना पांच लाख कार्बन सिंक करने की व्यवस्था

पांच साल के दौरान कोयला व लिग्नाइट कंपनियों ने मिलकर 56 हजार हेक्टेयर जमीन पर पौधे लगाए हैं। वर्ष 2030 तक 30 हजार हेक्टेयर जमीन पर और पौधारोपण करने की योजना है। इस योजना के तहत झारखंड में करीब दो दर्जन से अधिक स्थल को चिन्हित किया गया है। इसके तहत सालाना पांच लाख टन कार्बन डाईआक्साइड के कार्बन सिंक करने की योजना है।

***Date*:** 11-09-2021
***Publication*:** The Times of India
***Edition*:** Kolkata

CIL e-auction bookings up 42% in Apr-Aug

TIMES NEWS NETWORK

Kolkata: Coal India's (CIL) e-auction bookings logged a robust 42% growth during April-August'21, on the back of a demand spike in coal based power generation and soaring international coal prices, compared to similar period year ago.

The booked volume during the ongoing fiscal, till August, is also more than a two-fold increase compared to nearly 20 million tonne (MT) over the pre pandemic April-August'19. According to CIL, it has booked 53.3 (MT) of coal in the first five months of FY'22, under the five auction categories.

This is nearly 16 MT higher compared to 37.5 MT of corresponding period FY'21. The add-on fetched was 30% over notified prices.

***Date*:** 11-09-2021
***Publication*:** Prabhat Khabar
***Edition*:** Dhanbad

बिजली संयंत्रों को कोल इंडिया के कोयला की आपूर्ति 20% बढ़ी

एजेंसियां ▷ नयी दिल्ली

सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि उसने इस महीने के पहले आठ दिन में बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति बढ़ायी है. इस दौरान प्रतिदिन औसतन 13.9 लाख टन कोयले की आपूर्ति की गयी. यह सालाना आधार पर लगभग 20 प्रतिशत अधिक है. देश में विभिन्न बिजलीघरों में कोयले की कमी के बीच कोल इंडिया का यह बयान महत्वपूर्ण है. कोल इंडिया ने कहा, सितंबर के पहले आठ दिनों में बिजली क्षेत्र को औसतन 13.9 लाख टन कोयले की आपूर्ति प्रतिदिन की गयी. पिछले साल सितंबर माह के दौरान इसी अवधि में औसतन आपूर्ति प्रतिदिन 11.6 लाख टन थी. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने कहा, कि कुल कोयला आपूर्ति को बढ़ा कर 18 लाख टन और बिजली क्षेत्र के लिए 14.5 लाख टन प्रतिदिन करने का लक्ष्य है. कोल इंडिया की इ-नीलामी बुकिंग में अप्रैल-अगस्त के दौरान 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई. इसका कारण कोयला आधारित बिजली उत्पादन संयंत्रों की मांग में वृद्धि तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतों में तेजी है.

***Date*:** 11-09-2021
***Publication*:** Prabhat Khabar
***Edition*:** Dhanbad

विविधीकरण. आने वाले समय में कोयले का उपयोग हो जायेगा कम

नये व्यवसाय से जुड़ने की राह में कोल इंडिया

- नये व्यवसाय के लिए दो कंपनियों का किया गया है गठन
- नाल्को के साथ भी संयुक्त उद्यम करने का समझौता
- मिथनॉल के उत्पादन भी 27301 करोड़ का निवेश

सत्येंद्र कुमार, धनबाद

कोयले के उत्पादन में एकाधिकार रखने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड व्यवसाय विविधीकरण की राह पर चल पड़ी है. अब कोयले के साथ कोल इंडिया अक्षय ऊर्जा, सोलर पॉवर जेनेरेशन, एल्युमीनियम समेल्टिंग (गलाने) आदि का व्यवसाय करेगी. कोल इंडिया बोर्ड इसके लिए 96 हजार करोड़ की राशि के निवेश पर मुहर लगा चुकी है. कंपनी ने नये व्यवसाय के लिए दो कंपनियों के गठन व नाल्को के साथ संयुक्त उद्यम करने का समझौता भी किया है. जानकारों के मुताबिक जस्ट ट्रांजिशन के कारण आने वाले समय में कोयले के उपयोग में भारी कमी होने वाली है. इस कारण कोल इंडिया द्वारा व्यवसाय का विविधीकरण अच्छा कदम है. वहीं यूनियन नेताओं ने भी कुछ सुझाव के साथ कोल इंडिया के इस फैसले का स्वागत किया है.

स्वागत योग्य कदम : रामानन्दन : ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन (सीटू) के महासचिव डीडी रामानंदन ने कोल इंडिया के इस फैसले को स्वागत योग्य कदम बताया. कहा पूरी दुनिया मे जस्ट ट्रांजिशन के तहत एनर्जी ट्रांजिशन शुरू हो चुका है. इस निर्णय से कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. कोल इंडिया कोयला क्षेत्रों के उन इलाकों में निवेश करे, नया व्यवसाय करे, जिन क्षेत्रों में खदानें बंद हो चुकी हैं, न कि गुजरात में.

क्या होगा नया व्यवसाय

उपलब्ध दस्तावेज के मुताबिक कोल इंडिया सरफेस कोल गैसीफिकेशन (सतह के कोयले का गैसीकरण) के तहत दनकुनी कोल कॉम्प्लेक्स में 5842 करोड़ व ईसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल व एसइसीएल में 27301 करोड़ का निवेश कर मिथनॉल का उत्पादन करेगी. दनकुनी में बनने वाले मिथनॉल की मार्केटिंग आइओसीएल करेगी. इसके लिए कोल इंडिया व आइओसीएल में एमओयू साइन हो चुका है. जबकि इसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल व एसइसीएल के लिए सीएमपीडीआई बिडिंग की प्रक्रिया शुरू करेगी.

संयुक्त उद्यम

कोल इंडिया एल्युमीनियम समेल्टिंग के व्यवसाय के लिए नाल्को के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम बनाया है. नीति आयोग ने इस संयुक्त उद्यम को अनुमति दे दी है. जबकि दीपम (निवेश और सार्वजनिक संपति प्रबंधन विभाग) से अनुमति का इंतजार है. इस संयुक्त उद्यम में कोल इंडिया 22012 करोड़ की राशि निवेश करेगी. अलुमिनियम समेल्टिंग के एक अन्य व्यवसाय में 28180 करोड़ का निवेश कर झारखंड व ओड़िसा में व्यवसाय करेगी. इसके लिए कोयला मंत्रालय, नीति आयोग, झारखंड व छत्तीसगढ़ सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है.

अक्षय ऊर्जा में प्रवेश

कोल इंडिया ने सीआइएल अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सीआइएल नवकरणीय ऊर्जा लिमिटेड नामक एक कंपनी बनायी है, जो अक्षय ऊर्जा (गैर-पारंपरिक) भाग के क्षेत्र में व्यवसाय करेगी. इसमें सौर, पवन, स्मॉल हाइड्रो, बायोमास, जियो-थर्मल, हाइड्रोजन, टाइडल आदि शामिल हैं. कोल इंडिया ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना हासिल कर अपने नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर अपनी पहली वाणिज्यिक सौर परियोजना प्राप्त किया है. कोल इंडिया ने एक अन्य अनुषंगी कंपनी सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड का गठन किया है, जो संपूर्ण सोलर पीवी विनिर्माण का व्यवसाय करेगा.

थर्मल प्रोजेक्ट

मध्यप्रदेश सरकार के मध्यप्रदेश पॉवर जेन्टरेटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) के साथ भागीदारी में 660 मेगावाट का एक पावर प्लांट लगायेगी, जो एमपी के चचाई में स्थापित होगा. इस पर कोल इंडिया 4666 करोड़ खर्च करेगी. सभी प्रोजेक्ट्स के टाइम लाइन भी तय किये गये है. इस बारे में दस्तावेज में कहा गया है कि वर्तमान महामारी के कारण एवं प्रशासनिक अनुमति के कारण थोड़ा विलंब हो रहा है.